साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544
चौपाल से भोपाल तक
भोपाल, सोमवार, 04-11 दिसंबर 2023 वर्ष-9, अंक-34
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

बालाघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक धान उत्पादक जिला

सड़ी 13 करोड़ की धान

» भंडारण करने वाली कंपनी के अधिकारियों पर केस दर्ज
» ओपन कैप में रखी गई धान को फटी त्रिपाल से ढांकवाया

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश में करोड़ों की धान रखरखाव के अभाव में सड़ने का मामला सामने आया है। ये खुलासा धान के स्टॉक की जांच के बाद हुआ है। प्रशासन ने भंडारण का कार्य करने वाली कंपनी के डायरेक्टर सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक धान उत्पादक जिला है। पिछले साल समर्थन मूल्य पर 40 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गई थी।

बालाघाट में वर्ष 2021-22 में उपार्जित धान के भंडार का अनुबंध गो ग्रीन कंपनी द्वारा जिले के डोगरिया, खापा, भेंडारा, चिकमारा, मोहाडी, वारा, पालडोंगरी, नंदलेसारा में स्थित ओपन कैप में किया गया था, लेकिन कंपनी द्वारा खुले आसमान के नीचे ओपन कैप में रखी गई धान को फटी त्रिपाल से ढांक दिया गया। इसके कारण बारिश और कड़ी धूप में धान खराब हो गई।

हजारों क्विंटल गायब

सुरक्षा के प्रबंध नहीं होने के कारण हजारों क्विंटल धान गायब हो गई। जांच में धान के स्टॉक में 6632.48 क्विंटल की कमी पाई गई, जिसकी कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए है। स्टेट वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन बालाघाट के जिला प्रबंधक रमेश पटले ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी।

एफआईआर दर्ज

बारासिवनी पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भंडारण करने वाली कंपनी गो ग्रीन डायरेक्टर संतोष साहू निवासी नवरंगपुरा अहम्दाबाद एवं स्टेट हेड सौरभ मालवीय, कपनी के सलाहकार अखिलेश बिसेन के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

खंडवाः सेंट्रल वेयर हाउस में सड़ रहा घुन लगा 250 मीट्रिक टन गेहूं

इधर, सीहोर से तीन साल पहले आया घुन लगा 250 मीट्रिक टन गेहूं खंडवा के सेंट्रल वेयर हाउस में सड़ रहा है। सेंट्रल वेयर हाउस इसकी देख रेख तो कर रहा है, लेकिन गेहूं खाने लायक नहीं होने से नागरिक आपूर्ति निगम ने इसका आवंटन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कंट्रोल दुकानों पर रोककर इसे बेचने का प्रस्ताव हाल ही में शासन को भेजा है। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद भारतीय खाद्य निगम गेहूं का उठाव करेगा। साल 2020 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन में बांटने के लिए सीहोर जिले से 2600 मीट्रिक टन घुन लगा गेहूं आया था। इसमें आधे से अधिक गेहूं का आवंटन नागरिक आपूर्ति निगम ने खरगोन और बुरहानपुर जिले में भी किया था। लेकिन अधिक मात्रा में घुन लगा होने की शिकायत के बाद विभाग ने इसका आवंटन कंट्रोल दुकानों पर रोक दिया। नागरिक आपूर्ति निगम अब इस गेहूं को बेचने के लिए प्रस्ताव बनाकर मप्र शासन के खाद्य एवं आपूर्ति निगम को भेजेगा।

पुआल जलाने की समस्या कम करेगा वैरायटी धान

खाद-पानी कम और औसत उत्पादन 65 क्विंटल हेक्टेयर

भोपाल। जागत गांव हमार

पुआल जलाने की समस्या को कम करने वाली धान की नई प्रभेद बीआरआर 2183 विकसित की गई है। इसके उत्पादन में खाद और पानी 30 से 35 प्रतिशत कम लगेगा। पौधे की लंबाई कम (110) सेमी) होगी और औसत उत्पादन 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलेगा। यह अधिक पैदावार वाले अन्य वैरायटी से 15-20 दिन पहले तैयार हो जाएगी। इससे खेत अक्टूबर के अंत या देरी से बोवनी में नवंबर के पहले सप्ताह में खाली हो जाएगी और इसका पुआल भी आसानी से खेत में गल जाता है।

बीएयू के वैज्ञानिकों से ईजाद की नई किस्म- बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉ. प्रकाश सिंह के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने इसे इजाद किया है। इस धान की वैरायटी को बिहार, यूपी, झारखंड, ओडिसा, हरियाणा, गुजरात सहित 6 राज्यों के किसानों को लाभ देगा। इन राज्यों के लिए अखिल भारतीय चावल सुधार परियोजना की 59वीं वार्षिक बैठक में केन्द्रीय प्रभेद विमोचन समिति अनुशंसा मिलने की पूरी संभावना है। वर्षा पर निर्भर और सीमित सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है। यह जलवायु अनुकूल किस्म है।

फसल में बीमारी और कीट भी कम लगेंगे

यह प्रभेद कंडुआ-लेड़ा, जीवाणु झुलसा, अच्छद अंगमारी-गलका एवं झोंका रोग के प्रति प्रतिरोधी है। तना छेदक, भूरा कोट-बीएचपी एवं पतीलपेटक के प्रति सहनशील है। इस किस्म में प्रति पौध 18-20 कल्ले जिसमें बालियां होती है। प्रत्येक बालियां 28-30 सेंटीमीटर लंबी, जिसमें दानों की संख्या 300- 450 तक होती है । 1000 दानों का वजन 20 से 21 ग्राम होता है, इसके दाने का रंग सुनहरा, मंसूरी या स्वर्णा जैसा होता है। धान से 65 प्रतिशत से अधिक चावल निकलता है। चावल भी मुलायम एवं भुरभुरा होता है।

अंतिम चरण में परीक्षण

परीक्षण पिछले तीन साल से बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में किया जा रहा है। बिहार में किशनगंज, सहरसा, भागलपुर, बांका, लखीसराय, समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, नालंदा, औरंगाबाद, गया, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर के 50 से अधिक प्रगतिशील कृषकों के यहां मिनी किट के माध्यम से किया गया तो बेहतर परिणाम मिले।

जगाई उम्मीदः आईसर के वैज्ञानिकों ने तैयार किया जीनोम अनुक्रमण

गुणकारी जामुन बनेगा कैंसर-मधुमेह के इलाज का कारगर नुस्खा

भोपाल। जागत गांव हमार

राजधानी में स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईसर) के वैज्ञानिकों ने जामुन का जीनोम अनुक्रमण तैयार कर इसके और भी औषधीय गुणों की पहचान की है। इसमें मौजूद एंटीआक्सीडेंट, एंटी फंगल और एंटी वायरल गुण अब जल्द ही कैंसर, डायबिटीज जैसी कई बड़ी बीमारियों के लिए रामबाण नुस्खा साबित होंगे। आईसर के वैज्ञानिको का दावा है कि अब तक जामुन के पौधे का जीनोम अनुक्रम नहीं किया गया था, यह दुनिया का पहला जीनोम अनुक्रमण है। आईसर के बायोलाजिकल साइंसेज विभाग के प्रो. विनीत के शर्मा ने बताया कि जीनोम सिक्वेंसिंग की मदद से जामुन के फल, बीज और छाल के कुछ विशिष्ट गुणों की पहचान की गई है। अब इसकी मदद से कैंसर, अल्सर, डायबिटीज सहित अन्य बड़ी बीमारियों का भी उपचार हो सकेगा। उन्होंने इसे चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी जीत बताते हुए कहा कि इसके गुणों को पहचानने के लिए वैज्ञानिक लंबे समय से प्रयासरत थे। अब जाकर यह उपलब्धि हासिल हुई है। शोध का प्रकाशन अंतरराष्ट्रीय जर्नल फ्रंटियर इन प्लांट सांइस में हुआ है। इस शोध में शोधार्थी अभिषेक चक्रवती, श्रृति महजन, मनोहर बिष्ट ने सहयोग किया है।

इन तकनीकों से मिली मदद

जीनोम अनुक्रमण से पता चला है कि जामुन के पेड़ की 1200 प्रजातियां होती हैं। ये सभी साइजेजियम परिवार की ही प्रजाति हैं। इस पौधे में 61 हजार जीन्स पाए जाते हैं। जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए एलुमिना, टेनेक्स व नैनोपोर तकनीक का उपयोग किया गया है। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि जामुन के बीज में जैम्बोली पाए जाते हैं। इस कारण यह एंटी डायबिटिक, एंटी अल्सर, एंटी फंगल और एंटीआक्सीडेंट की तरह काम करता है। वैज्ञानिकों को इस जीनोम अनुक्रमण से यह भी पता चला कि इसमें कौन-कौन से जीन्स हैं, जिस कारण इसका महत्व बढ़ गया है। इस अनुक्रमण को पूरा करने में वैज्ञानिकों को ढाई साल का समय लगा।

यह है जीनोम अनुक्रमण

जीनोम उपक्रमण की मदद से हम किसी पौधों में छिपे गुणों का पता लगाते हैं। यह अनुक्रमण एक प्रकार का कोड होता है, जो डीएनए के अंदर एडेनीन (ए), गुआनीन (जी), साइटोसीन (सी) और थाइमीन(टी) के रूप में रहता है। ये चारों क्रम बदल-बदलकर डीएनए में सजे रहते हैं। उदाहरण के तौर पर एजीसीटी, एसीजीटी, एटीजीसी...। यह अनुक्रमण पौधों में हजारों से लेकर लाखों, करोड़ों तक हो सकते हैं। ये जीनोम अनुक्रमण ही जीन्स बनाते हैं। इसकी मदद से यह भी पता लगाया जाता है कि ये जीन्स कैसे काम करते हैं और इसके बगल में कौन-कौन से जीन्स हैं। ये आपस में मिलकर भी अलग-अलग तरह के गुण विकसित करते हैं। वैज्ञानिक इन्हीं जीन्स का अध्ययन कर किसी पौधे का असली गुण पहचानते हैं।

आईसर के बायोलाजिकल साइंसेज विभाग के वैज्ञानियों द्वारा जामुन के अलावा अब तक गिलोय, आंवला, पीपल, बरगद, एलोवेरा, अदरक पर जीनोम अनुक्रमण किया गया है। जामुन के पौधे का जीनोम अनुक्रमण कर इसकी प्रजाति और औषधीय गुणों के बारे में पता लगाया गया है। इसकी मदद से इसका उपयोग कई बड़ी बीमारियों की दवाइयों में किया जा सकेगा। अब तक जामुन के पौधे का जीनोम अनुक्रम नहीं किया गया था, यह दुनिया का पहला जीनोम अनुक्रमण है।

प्रो. विनीत के शर्मा, वैज्ञानिक, बायोलाजिकल साइंसेज विभाग, आईसर, भोपाल

-खेत जलमग्न होने से फसल बर्बाद, जिम्मेदरों ने नहीं ली सुध

जल संसाधन विभाग की लापरवाही से किसानों की मेहनत पर फिरा पानी

दमोह। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के दमोह जिले के तेंदूखेड़ा ब्लॉक में आने वाले बैलढाना गांव के दर्जनों किसानों के खेत में नहर का पानी भरने से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। यहां पर सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने बिना किसी जानकारी के तालाब की नहर खोल दी। नहरों में कचरा जमा हुआ था इसलिए नहरों का पानी ऊपर से होकर सीधे खेतों में पहुंच गया। इस जल भराव के कारण किसानों द्वारा खेतों में की गई बुवाई अब खराब हो जाएगी और उनका अनाज भी बर्बाद हो जाएगा। नहर का पानी तालाब में भरने की खबर कर्मचारियों को मिली तो उन्होंने नहर को बंद कर दिया। लेकिन तब तक काफी खेतों में पानी भर चुका था।

तालाब बैलढाना रैयत गांव में बना है और नहर पांजी गांव तक बनाई गई हैं। किसान सूरज केवट ने बताया कि रैयत में बने तालाब से जो नहर गई हैं, उनमें काफी कचरा जमा है। पानी की निकासी नहीं होती है। उसी तालाब से पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण ये हालत बने हैं।

नहरों में कचरा जमा होने से पानी ऊपर से खेतों में पहुंच गया

नहरें क्षतिग्रस्त किसान कमल केवट ने बताया कि नहरें क्षतिग्रस्त हैं और कचरे से भरी हुई हैं। पानी की निकासी होती नहीं हैं। उसके बाद भी पानी पहुंचाने के लिए तालाब का पानी छोड़ा गया और पानी आगे नहीं जाकर नहरों के ऊपर से खेतों में भर गया, जिसके कारण खेत जलमग्न हो गए।

फसल होगी नष्ट

किसान लोकराम केवट ने बताया कि तेज बहाव होने और नहरों से निकासी न होने के कारण तालाब का पानी खेतों में भर गया है और खेत जलमग्न हो गए हैं। ऐसी स्थिति में उनमें लगी फसल पूरी तरह खराब होने की कगार पर पहुंच गई है।

छोटे थे गेहूं के पौधे

किसान हलवा केवट और किसान गणेश केवट ने बताया कि गेहूं की फसल लगाई थी जो काफी छोटी थी। लेकिन तेज बहाव से पानी खेतों में पहुंचा और खेत जलमग्न हो गए। ऐसी स्थिति में जो फसल उग रही थी, वह पूरी तरह नष्ट हो गई।

पानी किसानों की मांग पर ही छोड़ा जाता है। नहरों की कहीं-कहीं साफ-सफाई चल रही है। अगर किसानों के खेतों में पानी भर गया है तो पता करेंगे किसकी लापरवाही से हुआ है।

राहुल जैन, एसडीओ,
जल संसाधन विभाग, दमोह

2018 में चुनाव-प्रचार के दौरान मोदी ने लिया था नाम

झाबुआ में महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी चंपा निनामा

-कड़कनाथ का पालन कर बनीं आर्थिक रूप से सक्षम

झाबुआ। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के पारा क्षेत्र के ग्राम धमोई की रहने वाली चंपा निनामा ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। वह शीतला माता के नाम से स्वयं सहायता समूह चलाने के साथ नवदीप संकुल स्तरीय संगठन पारा की अध्यक्ष भी हैं। इस संगठन से 50 गांवों की महिलाएं जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झाबुआ आगमन पर चंपा भी इन दिनों सुर्खियों में हैं क्योंकि प्रधानमंत्री पूर्व में न केवल उनसे संवाद कर चुके हैं, बल्कि 20 नवंबर 2018 को झाबुआ में चुनावी सभा के दौरान उन्होंने मंच से चंपा का नाम भी लिया था। दरअसल, चंपा निनामा झाबुआ के धमोई गांव की रहने वाली हैं। कभी दो वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करने वाली चंपा आज हर साल लाखों रुपए कमा रही हैं।

चंपा कड़कनाथ पालन के जरिए आर्थिक रूप से सक्षम बनीं और अब किराना दुकान भी चला रही हैं। पांच साल पहले तक जहां कड़कनाथ मुर्गे पालन के जरिए चंपा सलाना एक लाख रुपए मुनाफा कमा रही थीं तो अब हर महीने की कमाई ही करीब 50 हजार पहुंच गई है।

इस तरह सुर्खियों में आई थीं चंपा

प्रधानमंत्री के झाबुआ आगमन पर चंपा भी इन दिनों सुर्खियों में हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पूर्व में न केवल उनसे संवाद कर चुके हैं, बल्कि 20 नवंबर 2018 को झाबुआ में चुनावी सभा के दौरान उन्होंने मंच से चंपा का नाम भी लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जून 2018 को नरेंद्र मोदी एप के जरिए कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ में चंपा निनामा से सीधे संवाद किया था। इस दौरान चंपा हाथ में कड़कनाथ लेकर आई थीं।

पीएम कहा था- अरे! वाह चंपा

पीएम मोदी से चर्चा करते हुए चंपा ने उस दौरान अपनी आर्थिक प्रगति से अवगत कराते हुए कहा था- कड़कनाथ पालन से उसकी जिंदगी बदल गई, पहले वह दाहोद-अहमदाबाद तक मजदूरी करने जाती थीं। इस पर प्रधानमंत्री की मुंह से निकला अरे वाह! चूंकि चंपा उस वक्त चांदी के गहने पहने हुई थीं तो प्रधानमंत्री बोले आपने इतने गहने पहन रखे हैं इससे ही लगता है कि आपकी आवक बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ने चंपा से उसके पास अभी कितने कड़कनाथ हैं और गांव की कितनी महिलाएं इसका पालन कर रही हैं इसे लेकर भी सवाल किए थे।

देश की तीन राज्यों में 90 फीसदी पैदावार

सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश है अव्वल

भोपाल। जागत गांव हमार

सोयाबीन भारत की एक महत्वपूर्ण फसल है। वहीं भारत सोयाबीन उत्पादन के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर है। गौरतलब है कि सोयाबीन को पीला सोना भी कहा जाता है। सोयाबीन का इस्तेमाल कई चीजों में किया जाता है। इससे तेल भी निकाला जाता है। इसके अलावा सोयाबीन से सोया बड़ी, सोया दूध, सोया पनीर आदि खाद्य सामाग्री भी बनाई जाती है। सोयाबीन तिलहन फसलों में आता है। सोयाबीन का उत्पादन भारत के लगभग सभी राज्यों होता है। वहीं सोयाबीन खाने के कई फायदे भी हैं। इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन-ई, विटामिन-बी, थायमिन और अमीनो अम्ल शामिल हैं। भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। यानी सोयाबीन उत्पादन के मामले में ये राज्य अव्वल है।

मप्र की हिस्सेदारी 48.07 फीसदी

मध्यप्रदेश के किसान हर साल बंपर सोयाबीन का उत्पादन करते हैं। देश की कुल सोयाबीन उत्पादन में मप्र का 48.07 फीसदी की हिस्सेदारी है। यहां की मिट्टी और जलवायु सोयाबीन की खेती के लिए बेहतर मानी जाती है। सोयाबीन को आम लोगों से लेकर जिम करने वाले लोग भी प्रोटीन के सेवन के लिए सोयाबीन को अपनी आहार में शामिल करते हैं।

कड़कनाथ झाबुआ की शान

नवंबर 2018 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ में कॉलेज मैदान पर चुनावी सभा लेने आए थे तो उस वक्त उन्होंने मंच से चंपा का नाम लिया था। मोदी बोले थे-मैंने चंपाबेन निनामा से बात की थी। वह कड़कनाथ मुर्गे को लेकर आईं थीं। उसने कहा था ये हमारे झाबुआ की आन बान शान कड़कनाथ है। ये कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ की समृद्ध विरासत, आर्थिक शक्ति और पूरे क्षेत्र को कड़क बनाने का काम करता है।

कड़कनाथ से कैसे बदली जिंदगी

मजदूरी करने वाली चंपा ने कड़कनाथ मुर्गे का पालन शुरू किया। शुरुआती दौर में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन फिर भी इससे उसकी सालाना कमाई एक लाख रुपए तक हो जाती थी लेकिन पिछले पांच साल में धीरे धीरे आय बढ़ती रही और अब हर महीने कम से कम पचास हजार रुपए कमाई कर रहीं हैं यानि सालाना 6 लाख रुपए। चंपा किराना दुकान भी चलाती हैं।

दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र

उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में इस राज्य की हिस्सेदारी 35.78 फीसदी है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के (2021-22) आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन के पैदावार में तीसरे स्थान पर राजस्थान है। यहां के किसान हर साल 8.49 फीसदी सोयाबीन का उत्पादन करते हैं। वहीं ये तीनों राज्य मिलकर 90 फीसदी सोयाबीन का उत्पादन करते हैं।

किसानों ने प्रशासन से जांच कर कार्रवाई की मांग

खेतों में रखा धान, खरीदी प्रारंभ नहीं, 50 क्विंटल उठा ले गए चोर

जबलपुर। जागत गांव हमार

भीटा, उमरिया, कजरवारा, टेमर के किसानों में भारी आक्रोश है। के खेतों में रखी हजारों क्विंटल धान में से चोरों द्वारा 24-25 नवंबर के बीच की रात में करीब 50 क्विंटल धान चोरी कर ली गई। यहां के किसानों के कृषि पंपों से बिजली की केबल काट कर चोरी की जा रही है, नोजल, कल्टिवेटर, पाइप की चोरी की जा रही है। वन विभाग की जमीन में पश्चिम बंगाल से आए रोहंगिया ने अवैध रूप से जंगल में अतिक्रमण कर बिल्डिंग बना कर बेचने का धंधा किया जा रहा है, डेरा में गधे लेकर आए रोहंगिया इस भेड़-बकरी के साथ रात्रि में अवैध कार्य भी कर रहे है। जंगली पौधों को खराब कर रहे हैं। जंगल सुरक्षा के लिए लगाई गई जालियां काट कर मकान बनाए जा रहे है, मुनायरे उखाड़ कर अलग कर रहे है, चोरी की बिजली जला रहे, अवैध रूप से ईपिक कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवा रहे है, यहां हो रही चोरियों में इनके भी हाथ हो सकते है। इस संबंध में किसानों ने प्रशासन से जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

किसानों ने की गश्त की मांग

किसानों को राहत देने के लिए प्रशासन को चाहिए की चोरी रोकने के लिए राजस्व विभाग या पुलिस विभाग के अधिकारियों को किसानों की धान जहां खेतों में खुली पड़ी हुई है उसी जगह पर सुरक्षा की दृष्टि से गश्त लगाने के निर्देश जारी किए जाएं शासन से यह भी मांग है कि शासन तत्काल सोसाइटी में धान खरीदना प्रारंभ कर दे, जिससे किसान अपनी धान सोसाइटी में ले जाकर के बेच सकें। क्षेत्रीय किसान सोहन लाल यादव, रज्जू पटेल, राजकुमार पटेल, अभय उपाध्याय, बालकुमार चौकसे, राजेश चौकसे, अशोक पटेल, गुड्डू पटेल, मुकेश पटेल ठेकेदार ने चोरों के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं किसानों को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।

पीड़ित किसान परेशान

खुले में पिगरी, उमरिया के किनारे बैजनाथ यादव के खेत के पास रखी धान के लगे ढेर में से चोर धान चोरी करके ले गए, गई से किसानों के पंपों में लगी केबिल भी काट कर चोरी की गई है, यहां पर किसानों द्वारा जो अपनी धान पर निशान लगाए गए थे उन निशानों के बीच में से धान चोरी दिखाई दे रही है। किसानों की धान सोसाइटी में नहीं खरीदी जा रही है इसलिए खुले में धान रखी है, धान मजबूरी में खेतों में डालने के लिए किसान मजबूर है, मेहनत से पैदा की गई इस फसल की हो रही चोरी से किसान भारी परेशान हैं।

इरी को गूगल से मिले 16 करोड़ रुपए

देश में अब नई तकनीक से होगा चावल का उत्पादन

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में अब चावल के उत्पादन में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा।

इसके लिए अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (इरी) को गूगल से दो मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 16 करोड़ 67 लाख रुपये) का अनुदान मिला है। इससे विश्व के चावल उत्पादन वाले देशों के किसान एआई की सलाह पर स्मार्ट जलवायु में चावल का उत्पादन बढ़ा सकेंगे। संस्थान के निदेशक डॉ. सुधांशु सिंह ने बताया कि अत्यधिक जलवायु परिवर्तनशीलता के कारण चावल उत्पादन के सामने कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। इसका समाना करने के लिए नई तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। इसी क्रम में एआई, आईओटी, और मशीन लर्निंग तकनीकी भी चावल के उत्पादन में सहयोगी होगी। इसकी सलाह से स्मार्ट जलवायु में चावल का उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। इरी के वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के अनुकूल उन्नत प्रजनन से नई प्राजतियों और अनुकूलित कृषि के तरीकों को विकसित करने पर लगातार काम कर रहे हैं। वाराणसी में स्थित, इरी के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र में (आइसार्क) जलवायु-अनुकूल किस्मों के तेजी से विकास के लिए स्पीडब्रीड की अत्याधुनिक

आधी आबादी का प्रमुख भोजन चावल

निदेशक ने कहा कि दुनिया की आधी आबादी का प्रमुख भोजन चावल है। एशिया इसके उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। मगर हम जलवायु परिवर्तन, अजैविक तनाव और पारंपरिक प्रबंधन क्रियाओं के साथ पारंपरिक फसल स्थापना विधियां जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इरी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करने में लगा है। इसके लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हितधारकों का भी सहयोग कर रहा है। वाराणसी के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र में जलवायु-अनुकूल किस्मों के तेजी से विकास के लिए स्पीड ब्रीड की अति उन्नत सुविधा भी उपलब्ध कराने में लगा है।

20 लाख क्विंटल तक उत्पादन होगा कम

इस बार मूंग की फसल के चलते गेहूं का रकबा घटा

नर्मदापुरम। जागत गांव हमार

जिले में अब तक गेहूं की मात्र 21 फीसदी ही बोवनी हो पाई है, जबकि चने की बोवनी 78 फीसदी हो चुकी है। हालांकि कृषि अधिकारी का कहना है कि जल्द ही बोवनी का लक्ष्य पूरा होगा। नर्मदापुरम जिले में लगभग 3 लाख 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बोवनी का लक्ष्य रखा है। जिसमें गेहूं का रकबा 2.46 हजार हेक्टेयर एवं चना का रकबा 70 हजार हेक्टेयर रखा है। बचा हुए शेष रकबे में अन्य फसलों को लिया जाना है। इसके साथ ही इस वर्ष सरसों के रकबे में बढ़ोतरी हुई है। इस बार सरसों 10 हजार हेक्टेयर बढ़ा है। इस बार मूंग की फसल के चलते गेहूं का रकबा घटा दिया गया है, जबकि उसके स्थान पर चना के रकबे में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल की बात करें तो जिलेभर में 64 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में चना की फसल ली गई थी। इस बार करीब 70 से 80 हजार हेक्टेयर चना की बोवनी होने वाली है। इस तरह चने का रकबा इस वर्ष करीब 10 हजार हेक्टेयर बढ़ गया है। किसानों ने बताया कि इस बार चने का रकबा बढ़ने का कारण जल्द खेत खाली होने के बाद मूंग का बोना बताया जा रहा है। चना कम पानी की फसल होने से किसान उसकी ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इसकी फसल जल्द ही किसानों के पास आ जाती है। साथ ही कीमत भी अच्छी मिलती है। इसके बाद किसान मूंग की बोनी कर लेते हैं।

गेहूं उत्पादन पर पड़ेगा असर

जिले मे पिछले वर्ष 2.56 हजार हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी की गई थी. गेहूं का करीब 10,000 हेक्टेयर रकबा कम होने से उत्पादन कम होगा। करीब 60 लाख क्विंटल से अधिक गेहूं का उत्पादन पिछले साल हुआ था, जो इस बार घटकर 40 से 45 लाख क्विंटल रहेगा। किसानों को मूंग के लिए ज्यादा समय मिलने से और चना जल्द आने से चने का रुझान बढ़ा है। इससे गेहूं के रकबे में कमी आएगी, जबकि चना सहित अन्य फसलों का रकबा बढ़ जाएगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी के नाम लिखा सामूहिक पत्र

1500 किसानों ने मांगी आत्मदाह की अनुमति

बुरहानपुर। जागत गांव हमार

शहर से 40 किलोमीटर दूर खकनार क्षेत्र के ग्राम पांगरी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इसके चलते गांव के करीब डेढ़ हजार किसानों ने 1500 किसानों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सामूहिक रूप से आत्म दाह की अनुमति मांगी है। मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इस परियोजना का काम जल्दी शुरू होने जा रहा है। लेकिन यहां तीन गांव के किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल, यहां के डेढ़ हजार किसान शासन की मुआवजा वितरण गाइड लाइन से संतुष्ट नहीं है। इसको लेकर जल संसाधन विभाग ने शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा है जिसमें प्रति हेक्टेयर 17.71 लाख का मुआवजा वितरण प्रस्ताव शामिल है।

किसानों ने बताया कि राज्य शासन की मौज वितरण गाइडलाइन से असंतुष्ट होकर खकनार तहसील के तीन गांव पांगरी बसली और नागझिरी के 1500 से अधिक किसान प्रभावित हो रहे हैं। किसानों ने सामूहिक रूप से एक पत्र राष्ट्रपति को भेजा है जिसमें किसानों ने कहा है कि पांगरी सिंचाई परियोजना का काम बिना मोबाइल से तय किए शुरू होता है तो यह सभी किसान सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे।

किसानों ने रोका काम

सिंचाई परियोजना के तहत पांगरी में जल संसाधन विभाग के सभी इंजीनियर इंद्रजीत उमरलिया बन बांधने वाले स्थान पर झंडी लगाने गए थे तभी किसानों ने उन्हें झड़ी लगाने से रोक दिया। इसके बाद किसानों ने एक बैठक ली और उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भेजा।

राष्ट्रपति को भेजे पत्र ये लिखा

किसानों ने पत्र में लिखा है कि ग्राम पांगरी में सिंचाई बांध परियोजना प्रस्तावित है। किसानों का कहना है कि 11 माह से बांध प्रभावित किसान न्याय उचित मौज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। किसानों ने राष्ट्रपति को पत्र में कहा है कि जब तक मूल्य निर्धारण नहीं हो जाता और मुआवजा नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रकार का बांध संबंधित कोई भी काम यहां शुरू नहीं किया जाना चाहिए। हमारे विरोध के बावजूद भी यहां बांध का काम शुरू होता है तो हम सभी को सामूहिक आत्मदाह की अनुमति प्रदान की जाए।

अमरूद की उत्पादन की उन्नत तकनीक और रोगों की रोकथाम

दिनेश कुमार कुलदीप, डॉ. एन आर रंगारे, डॉ. मनमोहन सिंह भूरिया, मनीष कुमार, नीलेन्द्र सिंह वर्मा, डॉ सौरव शुमा,
जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर विषय विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र,खंडवा(म.प्र.)

अमरूद मिर्टेन्सी कुल का पौधा है, जो सिडियम वंश के अंतर्गत आता है। इसका वैज्ञानिक नाम सिडियम ग्वाजावा है। इसका उत्पत्ति स्थान उष्ण कटिबंधीय अमेरिका को माना जाता है। अमरुद भारत का एक प्रसिद्ध फल है। अमरूद ताजे रूप में खाने के अलावा कई मूल्यवर्धक उत्पाद जैसे जैम, जैली, आरटीएस, आईसक्रीम, चीज, टाफी इत्यादि बनाने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। इसके फलों में पैक्टिन की अधिकता होने के कारण उच्च गुणवत्ता की जैली बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।

अमरूद को गर्म एवं शुष्क जलवायु में अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। अमरूद की खेती के लिए 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अनुकूल होता है, परंतु अधिक वर्षा अमरूद की खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। अमरूद की फसल सूखे को आसानी से सहन कर लेती है।

अमरूद के लिए मृदा: अमरूद को लगभग सभी प्रकार की मृदा में उगा सकते हैं। परंतु उपजाऊ बलुई दोमट मृदा अमरूद उत्पादन में अच्छी मानी जाती है। अमरूद की खेती 6 से 7.5 पी.एच. मान वाली मृदा में आसानी से की जा सकती है। मृदा का पी एच 7.5 से अधिक होने पर उखठा रोग की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है।

प्रसारण एवं प्रवर्धन: अमरूद का प्रवर्धन बीज और वानस्पतिक भाग से किया जा सकता है। परंतु बीज से तैयार पौधे की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। वानस्पतिक भाग से तैयार पौधे ही अच्छे उत्पादन के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। व्यवसायिक प्रवर्धन के लिए गूटी विधि प्रयोग किया जाता है।

अमरूद के रोपण का समय: पौधों को लगाने का सही समय जुलाई से अगस्त माह होता है। लेकिन कम सिंचाई वाले स्थानों पर फरवरी से मार्च में भी लगा सकते हैं।

गड्ढों का आकार: अमरूद के पौधों को रोपने के लिए 60 × 60 × 60 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे रोपने के 20 से 25 दिन पहले तैयार किए जाते हैं। गड्ढों को भरने के लिए 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद, 500 ग्राम फास्फेरस, 250 ग्राम पोटाश और 100 ग्राम मिथाइल पेराथिआन मृदा में अच्छी तरह से मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेमी ऊपर तक रोपने से 15 दिन पहले भर देते हैं।

पौधों से पौधों की दूरी: सामान्य तौर पर अमरूद को 5 × 5 मी. या 6 × 6 मी. पर लगाते हैं। परंतु सघन बागवानी प्रणाली में अमरूद को 2 × 1.5 मीटर या 3 × 3 मीटर पर लगाकर प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन लिया जा सकता है।

अमरूद में बहार का समय एवं बहार उपचार: अमरूद के पौधे में वर्ष में 3 बार फूल आते हैं। फूल के आने को ही बाहर कहते हैं। मृग बहार (जून-जुलाई) अम्बे बहार (फरवरी-मार्च) तथा हस्त बहार (सितंबर-अक्टूबर) में आती है। परंतु अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त करने के लिए वर्ष में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। वर्षा ऋतु में जो बहार आती हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। इसमें रोग एवं कीट का आक्रमण अधिक होता है इसलिए वर्षा ऋतु के फल को ना ले कर शरद ऋतु के फल को लेते हैं क्योंकि इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। वर्षा ऋतु की फसल को रोककर शरद ऋतु की फसल को लेते हैं तो उसे ही फलन या बहार उपचार कहते हैं।

बहार उपचार निम्न प्रकार से करते हैं: अमरूद के पेड़ों को फरवरी से मई के मध्य तक सिंचाई नहीं दी जानी चाहिए इस प्रकार पेड़ गर्मी के मौसम अप्रैल-मई के दौरान अपने पत्ते गिरा कर आराम करने के लिए चले जाते हैं। इस दौरान वृक्ष अपनी शाखाओं मे खाद्य सामग्री संरक्षण कर लेते हैं। जून के महीने में पेड़ों को खाद देकर सिंचाई की जाती है जिससे 20 से 25 दिनों के बाद पेड़ में विपुल मात्रा में फूल निकलते हैं। और वह सर्दियों के दौरान फल में परिपक्व हो जाते हैं। यूरिया का 10 से 20 प्रतिशत का छिड़काव तथा एनएए (100 पीपीएम) के घोल का छिड़काव करने से भी अमरूद के पौधों में आने वाली बहार में फूलों की संख्या अधिक होती है।

अमरूद की प्रमुख किस्में: भारत में अमरूद की कई सारी किस्में उगाई जाती है, परंतु 10 से 12 किस्में ज्यादा उगाई जाती हैं। इसमें इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ-49, चित्तीदार, ग्वालियर -27, बेहद कोकोनट, धारीदार, ललित, अर्का मृदुला, एप्पल कलर एवं संकर किस्मों में अर्का अमूल्य प्रमुख है।

इलाहाबाद सफेदा: फल का आकार मध्यम, गोलाकार एवं औसत वजन 180 ग्राम होता है। फल की सतह चिकनी, छिलका पीला गूदा मुलायम, रंग सफेद एंव मीठा होता है। इस किस्म को अधिक दिनों तक भंडारित कर सकते हैं।

लखनऊ- 49 (सरदार अमरूद): इसका फल आकार में बड़ा और खुरदरा होता है। गूदा मुलायम, सफेद तथा स्वाद मीठा होता है। इसकी उत्पादन क्षमता 130 से 155 किलोग्राम प्रति पौध प्रति साल है इसमें उखठा रोग कम लगता है।

चित्तीदार: सतह पर लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इसके बीज मुलायम तथा छोटे होते हैं। फल मध्यम, अंडाकार, चिकने हल्के पीले रंग के होते हैं। गूदा मुलायम, सफेद मीठा होता है।

एप्पलकलर: फल गोल, छिलका, गुलाबी या हरे रंग का होता है। फलों का गूदा मुलायम सफेद युक्त होता है।

अर्का मृदुला: फल मध्यम आकार, गूदा मुलायम एवं मीठा होता है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एवं भंडारण क्षमता भी अच्छी होती है।

अमरूद के रोग एवं प्रबंधन: 1: उखठा रोग: यह एक विनाशकारी रोग है। पेड़ की पत्तियां भूरे रंग की हो जाती है। पेड़ मुरझा जाता है, शाखाएं करके सूखने लगती हैं। यह रोग 7.5 से अधिक पीएच मान वाली मृदा में अधिक होता है। नियंत्रण के लिए पेड़ उखाड़ कर जला दें और गड्ढों को 1 ग्राम वाविस्टीन प्रति लीटर पानी के हिसाब से 20 ली. से उपचार करें।

एंथ्रेक्नोज बीमारी: इस रोग के लक्षण और पत्तियों पर दिखाई देते हैं। इस रोग में फल तथा पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। जो बाद में काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सिक्लोराइड के 0.3 प्रतिशत घोल का छिड़काव 15 दिन के अंतर में करना चाहिए एवं कार्बेंडाजिम 2-3 ग्राम प्रति ली. के हिसाब से दिसंबर में छिड़काव करना चाहिए।

फल चित्ती रोग : इस रोग में फलों पर भूरे और काले रंग के धब्बे बनने लगते हैं। रोग बढ़ने पर पत्तियों पर भी इसका देखा जा सकता है। अप्रैल से अगस्त महीने में पौधों में यह रोग अधिक पाया जाता है। इस रोग से बचने के लिए प्रति 15 लीटर टंकी मे 30-40 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिलाकर छिड़काव करें। आवश्यकता होने पर हर 15 दिनों के अंतराल पर 3 से 4 बार छिड़काव कर सकते हैं।

प्याज एवं लहसुन के प्रमुख रोगों एवं कीटों की रोकथाम

डॉ. एन आर रंगारे, दिनेश कुमार कुलदीप, डॉ. मनमोहन सिंह भूरिया
जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर

प्याज एवं लहसुन भारत में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसलें है। इनकों सलाद के रूप में, सब्जी में, आचार या चटनी बनाते समय प्रयोग में लाते हैं। प्याज एवं लहसुन में विभिन्न औषधीय गुण भी पाये जाते हैं। प्याज एवं लहसुन की खेती रबी मौसम में की जाती है लेकिन इनको खरीफ (वर्षा ऋतु) मौसम में भी उगाया जाता है। प्याज एवं लहसुन की फसल में अनेक रोग लगते हैं किन्तु कुछ ही विशेष रूप से हानिकारक हैं। इनकी रोकथाम अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा पूरा परिश्रम तथा फसल पर किया गया व्यय निरर्थक हो जाता है तथा किसानों को घोर निराशा व हानि होती है।

प्याज एवं लहसुन में लगने वाले प्रमुख रोग तथा उनकी रोकथाम के उपाय निम्नलिखित हैं-

क. प्याज व लहसुन की नर्सरी में लगने वाले रोग:
आर्द्रगलन (डैम्पिंग आफ): यह बीमारी प्राय: हर जगह जहां प्याज की पौध उगायी जाती है, मिलती है। यह मुख्य रूप से पीथियम, फ्यूजेरियम तथा राइजोक्टोनिया कवकों द्वारा होती है। इस बीमारी का प्रकोप खरीफ मौसम में ज्यादा होता है। यह रोग दो अवस्थाओं में होता है-

बीज अंकुरण के बाद, उसमें सड़न रोग लग जाता है जिससे पौध जमीन से उपर आने से पहले ही मर जाती है। बीज अंकुरण के 10-15 दिन बाद जब पौध जमीन की सतह से उपर निकल आती है तो इस रोग का प्रकोप दिखता है। पौध के जमीन की सतह पर लगे हुए स्थान पर सड़न दिखाई देती है और आगे पौध उसी सतह से गिरकर मर जाती है।

रोकथाम: बुवाई के लिए स्वस्थ बीज का चुनाव करना चाहिए। बुवाई से पूर्व बीज को थाइरम या कैप्टान 2.5 ग्राम प्रति कि.ग्रा बीज की दर से उपचारित कर लें। पौध शैय्या के उपरी भाग की मृदा में थाइरम के घोल (2.5 ग्राम प्रति ली. पानी) या बाविस्टीन के घोल (1.0 ग्राम प्रति ली. पानी) से 15 दिन पर छिड़काव करना चाहिए। जड़ और जमीन को ट्राइकोडर्मा विरडी के घोल (5.0 ग्राम प्रति ली. पानी) से 15 दिन पर छिड़काव करना चाहिए।

ख. प्याज व लहसुन की खेत में लगने वाले पर्णीय रोग:
बैंगनी धब्बा रोग (परपल ब्लाच): प्राय: यह बीमारी प्याज एवं लहसुन उगाने वाले सभी क्षेत्रों में पायी जाती है। इस बीमारी का कारण आल्टरनेरिया पोरी नामक कवक है। यह रोग प्याज की पत्तियों, तनों तथा बीज डंठलों पर लगती है। रोग ग्रस्त भाग पर सफेद भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जिनका मध्य भाग बाद में बैंगनी रंग का हो जाता है। रोग के लक्षण के लगभग दो सप्ताह पश्चात इन बैंगनी धब्बों पर पृष्ठीय बीजाणुओं के बनने से ये काले रंग के दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त पत्तियां झुलस जाती हैं तथा पत्ती और तने गिर जाते हैं जिसके कारण कन्द और बील नहीं बन पाते।

रोकथाम: अच्छी रोग प्रतिरोधी प्रजाति के बीज का प्रयोग करना चाहिए। 2-3 साल का फसल-चक्र अपनाना चाहिए। प्याज से संबंधित चक्र शामिल नहीं करना चाहिए। पौध की रोपाई के 45 दिन बाद 0.25 प्रतिशत डाइथेन एम-45 या सिक्सर या 0.2 प्रतिशत धानुकाप या ब्लाइटाक्स-50 का चिपकने वाली दवा मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। बीमारी ज्यादा हो तो छिड़काव 3-4 बार प्रत्येक 10-15 दिन के अन्तराल पर करना चाहिए।

झुलसा रोग (स्टेमफीलियम ब्लाइट) लक्षण: यह रोग स्टेमफीलियम बेसिकेरियम नामक कवक द्वारा फैलता है। यह रोग पत्तियों और बीज के डंठलों पर पहले छोटे-छोटे सफेद और हलके पीले धब्बों के रूप में पाया जाता है और अन्त में ये गहरे भूरे या काले रंग के हो जाते हैं। पत्तियां धीरे-धीरे जाती हैं और कन्दों का विकास नहीं हो पाता।

रोकथाम:स्वस्थ एवं अच्छी प्रजाति के बीज का प्रयोग करना चाहिए। लम्बा फसल-चक्र अपनाना चाहिए। पौध की रोपाई के 45 दिनों के बाद 0.25 प्रतिशत मैनकोजेब (डाइथेन एम-45) या सिक्सर (डाइथेन एम-45 . कार्बन्डाजिम) अथवा 0.2-0.3 प्रतिशत कॉपर आक्सीक्लोराइड (ब्लाइटाक्स- 50) का छिड़काव प्रत्येक 15 दिन के अन्तराल पर 3-4 बार करना चाहिए। जैविक विधियों का प्रयोग करना चाहिए।

मृदुरोमिल आसिता (डाउनी मिल्डयू) लक्षण: यह बीमारी पेरेनोस्पोरा डिस्ट्रक्टर नामक फफूंद के कारण होती है व जम्मू-कश्मीर तथा उत्तरी मैदानी भागों में पाई जाती है। इसके लक्षण सुबह जब पत्तियों पर ओस हो तो आसानी से देखे जा सकते है। पत्तियों तथा बीज डंठलों की सतह पर बैंगनी रोयेंदार वृद्धि इस रोग की पहचान है। रोग की सर्वांगी दशाओं में पौधा बौना हो जाता है। रोगी पौधे से प्राप्त कन्द आकार में छोटे होते हैं तथा इनकी भंडारण अवधि कम हो जाती है।

रोकथाम: हमेशा अच्छी प्रजाति के बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। पौध को लगाने से पहले खेतों की अच्छी तरह से जुताई करना चाहिए जिससे उसमें उपस्थित रोगाणु नष्ट हो जाये। बीमारी का प्रकोप होने पर 0.25 प्रतिशत मैनकोजेब अथवा कासु-बी या 0.2 प्रतिशत सल्फर युक्त कवकनाशी का घोल बनाकर 15 दिन के अन्तराल पर दो से तीन बार छिड़काव करना चाहिए।

प्याज का कण्ड (स्मट) लक्षण: इस रोग में रोगग्रस्त पत्तियों और बीज पत्तों पर काले रंग के फफोले बनते है जो बाद में फट जाते हैं और उसमें से रोगजनक फफूंदी के असंख्य बीजाणु काले रंग के चूर्ण के रूप में बाहर निकलते हैं और दूसरे स्वस्थ पौधों में रोग फैलाने में सहायक होते हैं। यह बीमारी यूरोस्सिटीस सीपली नामक फफूंद से फैलती है।

रोकथाम: हमेशा स्वस्थ एवं उत्तम कोटि के बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। बीज को बोने से पूर्व थाइरम या कैप्टान 2.0-2.5 ग्राम प्रति कि.ग्रा. की दर से उपचारित करें। दो-तीन वर्ष का फसल-चक्र अपनाना चाहिए।

वायु प्रदूषण: हर साल करीब 22 लाख जिंदगियां छीन रहा

ब्रिटिश मेडिकल जर्नल (बीएमजे) में प्रकाशित एक नई रिसर्च के मुताबिक घरों, इमारतों से बाहर वातावरण में मौजूद वायु प्रदूषण भारत में हर साल 21.8 लाख जिंदगियों को छीन रहा है। यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां वायु प्रदूषण इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगियों को लील रहा है। रिसर्च में जो आंकड़े साझा किए हैं उनके मुताबिक चीन में आउटडोर एयर पॉल्यूशन हर साल 24.4 लाख लोगों की मौत की वजह बन रहा है। वहीं यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाले वायु प्रदूषण दुनिया भर में हर साल करीब 51.3 लाख लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। इस जीवाश्म ईंधन का उपयोग उद्योग, बिजली उत्पादन और परिवहन जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है। बता दें कि अपने इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2019 के साथ-साथ वातावरण में मौजूद प्रदूषण के महीन कणों की मौजूदगी की जानकारी के लिए नासा के उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों की मदद ली है। साथ ही उन्होंने इसके लिए ऐसे मॉडलों का उपयोग किया है जो वातावरण की परिस्थितियों और एरोसोल के साथ-साथ स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कर सकते हैं। इनकी मदद से शोधकर्ताओं ने यह समझने का प्रयास किया है कि जीवाश्म ईंधन से होने वाला वायु प्रदूषण कितने लोगों की जान ले रहा है और यदि जीवाश्म ईंधन को स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बदल दिया जाए तो उससे लोगों के स्वास्थ्य को कितना फायदा होगा।

इस अध्ययन के जो नतीजे सामने आए हैं उनके मुताबिक दुनिया भर में 2019 के दौरान सभी स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण के चलते 83.4 लाख लोगों की असमय मृत्यु हो गई थी। इसके लिए प्रदूषण के महीन कण और ओजोन जैसे प्रदूषक जिम्मेवार थे।

इनमें से आधे से अधिक करीब 52 फीसदी मौतें हृदय सम्बन्धी रोगों और चयापचय से जुड़ी थी। वहीं अकेले 30 फीसदी मौतों के लिए वायु प्रदूषण से जुड़ी हृदय सम्बन्धी बीमारियां जिम्मेवार थी। इसी तरह 16 फीसदी मौतों की वजह स्ट्रोक, 16 फीसदी के लिए फेफड़े की बीमारी और छह फीसदी के लिए मधुमेह जैसी स्थिति जिम्मेवार थी। वहीं 20 फीसदी मौतों की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। इसके लिए उच्च रक्तचाप और न्यूरोडीजेनेरेटिव विकार जैसे अल्जाइमर और पार्किंसंस जिम्मेवार हो सकते हैं।

रिसर्च में वायु प्रदूषण से होने वाली इन 83.4 लाख मौतों के करीब 61 फीसदी के लिए केवल जीवाश्म ईंधन को जिम्मेवार माना है। ऐसे में शोधकर्ताओं का कहना है कि स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा जैसे समाधानों की मदद ली जाए तो इन मौतों को टाला जा सकता है।

बीपी-डायबिटीज जैसी बीमारियों के लिए है रामबाण

बड़े कमाल का है ये पहाड़ी फल कई औषधीय गुणों से भरपूर

नई दिल्ली/भोपाल। जागत गांव हमार

पहाड़ी क्षेत्रों में कई ऐसे फल पाए जाते हैं जो औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। ऐसा ही एक फल है घिंगारू, जो अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। यह फल खासकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाया जाता है। कुमाऊंनी में इसे घिंगारू, गढ़वाली में घिंघरू और नेपाली में घिंगारू के नाम से जाना जाता है। घिंघरू के फल सेब की तहत छोटे-छोटे होते हैं और इन्हें हिमालयन रेड बेरी, फायर थोर्न एप्पल या व्हाइट थोर्न भी कहा जाता है। लोग अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन घिंघरू पौधा चमत्कारी गुणों से भरपूर होता है।

पेनकिलर बनाने में इस्तेमाल- घिंगारू पर कई वैज्ञानिक शोध भी हो चुके हैं। जिससे पता चला है की घिंगारु का पौधा दर्द निवारक दवा बनाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह पौधा हमारे लिए बहुत उपयोगी है, चाहे वह जड़ हों या फल, फूल, पत्तियां या टहनियां। इस पौधे के हर हिस्से का अपना-अपना उपयोग है। जिसका इस्तेमाल किसी न किसी बीमारी के लिए किया जाता है। पहाड़ों क्षेत्रों में स्कूली बच्चे और गांव में जंगल जाने वाली महिलाएं इसे बड़े मजे के साथ खाती हैं। इसके फलों को सुखाकर चूर्ण बनाया जाता है। जिसे दही के साथ खाने से खूनी दस्त बंद हो जाते हैं।

कई बीमारियों के लिए कारगार

डायबिटीज में भी इस फल को काफी फायदेमंद माना जाता है। इलके फल और पत्तियों में इतने मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फलेमेट्री गुण होते हैं कि इसका इस्तेमाल हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह रोगों को ठीक करने में भी किया जा सकता है। इसके अलावा, यह बताया गया है कि घिंगारु खूनी दस्त को रोकने में भी अत्यंत प्रभावी है अगर आप खूनी दस्त से परेशान हैं, तो इसके फलों का सेवन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आप इसके फलों को सुखाकर चूर्ण बनाकर दही के साथ सेवन कर सकते हैं। इस तरीके से आप खूनी दस्त से जल्द ही निजात पा सकते हैं। घिंगारु के औषधीय गुण शरीर में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में भी मदद करते हैं। इस फल को खाने से याददाश्त भी तेज होती है।

खट्टा-मीठा होता है घिंघरू का स्वाद

इस फल में शुगर भी काफी मात्रा में पाई जाती है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। इसके अलावा, इसकी टहनी को दातून के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे दांतों का दर्द दूर होता है। घिंगारु को प्रोटीन का भी एक अच्छा सोर्स कहा जाता है। घिंगारु के छोटे-छोटे फल गुच्छों में पाए जाते हैं। यह फल अगस्त और सितंबर महीने में पकने पर नारंगी या गहरे लाल रंग के हो जाते हैं। इनका स्वाद हल्का खट्टा, कसैला और थोड़ा मीठा होता है। यह पौधा मध्यम आकार का होता है और इसकी शाखाएं कांटेदार और पत्ते गहरे रंग के होते हैं। यह पौधा 500 से 2700 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है।

राजस्थान को पीछे छोड़ यूपी बना नंबर वन

2022-23 में 9.2 मिलियन टन तक बढ़ा दूध उत्पादन

भोपाल। जागत गांव हमार

नेशनल मिल्क डे के मौके पर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केन्द्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 में दूध उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। बीते एक साल में दूध उत्पाादन 9.52 मिलियन टन बढ़ा है। दूध उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे बड़े राज्य के रूप में सामने आया है। इस खास मौके पर ये जानकारी खुद केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरषोत्तम रूपाला ने एक कार्यक्रम के दौरान साझा की है। उनका कहना है कि विश्व में कुल दूध उत्पादन में भी भारत की बादशाहत बरकरार है। वहीं, बीते 10 साल में दूध उत्पादन 146 से 230 मिलियन टन पर पहुंच गया है। गौरतलब रहे कि बीते कुछ साल में खासतौर पर घी और बटर का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। डेयरी एक्सपर्ट का मानना है कि अगर आने वाले वक्त में दूध उत्पादन सरप्लास होता है तो वो बेकार नहीं जाएगा। क्योंकि हमारे आसपास के देशों में दूध से बने प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है।

दूध उत्पादन के मामले में मंत्री ने बताए ये आंकड़े - केंद्रीय मंत्री रूपाला का कहना है कि 2022-23 के दौरान देश में कुल दूध उत्पादन 230.58 मिलियन टन अनुमानित है, जिसमें पिछले पांच साल में 22.81त्न की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि साल 2018-19 में दूध उत्पादन 187.75 मिलियन टन था। जबकि 2021-22 में 221.6 मिलियन टन हो गया था।

राजस्थान को पीछे छोड़ यूपी बना नंबर वन

डेयरी मंत्रालय की साल 2022-23 में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल दूध उत्पादन 230.58 मिलियन टन हुआ था। इसमे सबसे ज्यादा 15.72 फीसद योगदान यूपी का है। जबकि बीते साल यूपी की हिस्सेदारी 14.93 फीसद थी। वहीं बीते साल इस दौड़ में 15.05 फीसद की हिस्सेदारी के साथ राजस्थान पहला नंबर पर था। लेकिन इस साल यूपी ने राजस्थान को पीछे छोड़ दिया है। बीते साल तीसरे, चौथे और पांचवे नंबर पर मध्य प्रदेश 8.60, गुजरात 7.56 और आंध्रा प्रदेश का 6.97 फीसद नंबर के साथ थे।

देश का दूध कारोबार एक नजर में-

- कुल दूध उत्पादन में भारत का पहला नंबर है।
- भारत में दूध का कुल उत्पादन 230.58 मिलियन टन है।
- 2021-22 में दूध का उत्पादन 221.06 मिलियन टन था।
- 2020-21 में दूध का उत्पादन 209.96 मिलियन टन था।
- सभी नस्ल की 5.75 करोड़ गाय 11 करोड़ टन दूध दे रहीं।
- सभी नस्ल की 4.62 करोड़ भैंस 9.53 करोड़ टन दूध दे रहीं।
- नोट- पशुपालन मंत्रालय की 2021-22 की रिपोर्ट

कृषि मंत्री बोले-उपभोक्ताओं को भी मिलेगा फायदा

खेती-किसानी को आगे बढ़ाएगा सहकारिता आंदोलन

नई दिल्ली,

भोपाल। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सहकारिता मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा है, जहां किसान और कृषि है। किसानों के पास सब कुछ आसानी से पहुंचाने और उनकी परेशानी कम करने में सहकारिता क्षेत्र का योगदान अहम होगा। इसके लिए सोसाइटियों का सशक्त होना जरूरी है। सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए आज देश में पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है, उनकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराकर दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू की जा रही है। पैक्स पीडीएस दुकान चलाएं, पेट्रोल पंप, दवा दुकान व गैस एजेंसी भी चलाएं, इस पर भी काम हो रहा है। इससे न सिर्फ पैक्स सशक्त होंगे, बल्कि उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा। तोमर पूसा मेला मैदान में सहकार भारती

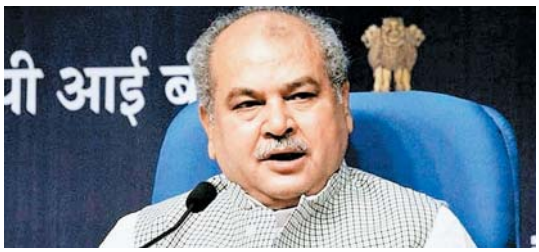

द्वारा आयोजित दो दिवसीय क्रेडिट सोसायटी राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी सोसाइटियां बनाई जा रही हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो लगातार इस बात की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है कि हर व्यक्ति सहकारिता के आंदोलन से जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। उनकी यह भी कोशिश रंग लाएगी।

विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद- तोमर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देशभर के 2.53 लाख पंचायतों तक पहुंच रही है। इसके जरिये केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने की कोशिश है। साथ ही 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। सहकारिता क्षेत्र सहित सभी देशवासी विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ें और अमृत काल में भारत को पूर्ण विकसित बनाने का संकल्प लें।

सहकारिता की यात्रा अधूरी - केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सहकार का भाव हमारे संस्कार में होने के बावजूद आजादी के 75 वर्ष बाद भी यह यात्रा अधूरी है, क्योंकि पहले काम करने वाले नेतृत्व में दृष्टि का अभाव था। नीति-नीयत की कमी थी, लेकिन आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त नेतृत्व है। उनके नेतृत्व में ऐसी सरकार काम कर रही है जिसकी दूर दृष्टि है, पक्का इरादा है और आगे बढ़ने का जज्बा है। पीएम मोदी ने पशुपालन, मत्स्यपालन, कौशल विकास और सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाने का महत्वपूर्ण काम किया है।

संस्कार के सहकार नहीं

तोमर ने कहा कि इस कार्यक्रम में क्रेडिट सोसाइटियों का एक जगह, एक उद्देश्य के लिए इतनी बड़ी संख्या में एकत्र होना बहुत महत्वपूर्ण व प्रसन्नता की बात है। हम सब यह भली-भांति जानते हैं कि बिना संस्कार के सहकार नहीं होता और बिना सहकार के उन्नति नहीं होती है। सहकार भारती, सहकारिता के क्षेत्र में समर्पित सेवाएं दे रही है। इसका उद्देश्य संस्कार से सहकार को आगे बढ़ाना है। सहकारिता का उद्देश्य देश के लिए नया नहीं है। सहकार का भाव हमारी आत्मा में बसता है। पहले गांवों में मकान कच्चे होते थे, लेकिन संबंध पक्के होते थे। सहकार के भाव के कारण गांव का कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं होता था।

धान की कटाई के बाद तुरंत इसका छिड़काव किया जाना चाहिए

पराली को खाद बना देगा ये कैप्सूल! बढ़ाएगा मिट्टी की उर्वरता

नई दिल्ली/भोपाल। जागत गांव हमार

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान(पूसा) ने पराली जलाने की समस्या से पैदा होने वाले प्रदूषण से छुटकारा दिलाने के लिए एक बायो डीकंपोजर बनाया था। यह बायो डीकंपोजर कुछ ही दिनों में पराली को गलाकर खाद बनाने की क्षमता रखता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके इस्तेमाल के दौरान प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना चाहिए, तभी इसका उपयोग ज्यादा प्रभावी साबित होगा।

मिट्टी की उर्वरता में बढ़ावा

वैज्ञानिकों के मुताबिक उचित उपयोग से केवल प्रभावी पराली निपटान में ही फायदा नहीं होगा बल्कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। पराली जलाने की घटनाएं उत्तर भारत में एक बड़ी समस्या बनकर आई है। इसके चलते दिल्ली-एनसीआर समेत पड़ोसी राज्यों में वायु प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी से जोड़ा गया है।

20 दिनों में लगभग 70-80 प्रतिशत पराली खाद में होगी तब्दील

इस साल नवंबर में एनसीआर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बार-बार 400 और 450 की गंभीर और गंभीर प्लस सीमा को पार कर गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि पूसा बायोडीकंपोजर एक माइक्रोबियल समाधान है जो लगभग 20 दिनों में लगभग 70-80 प्रतिशत पराली अवशेषों को खाद में बदल सकता है।

4 कैप्सूल से बना सकते हैं 25 लीटर तक घोल

पूसा इंस्टीट्यूट के मुताबिक बायो डिकंपोजर 4 कैप्सूल से 25 लीटर तक बायो डिकंपोजर घोल बनाया जा सकता है। 25 लीटर घोल में 500 लीटर पानी मिलाकर इसका छिड़काव ढाई एकड़ में किया जा सकता है। ये पराली को कुछ ही दिनों में ही सड़ाकर खाद बना सकता है। इसके लिए धान की कटाई के बाद तुरंत इसका छिड़काव किया जाना चाहिए। छिड़काव करने के बाद पराली को जल्द से जल्द मिट्टी में मिलाना या जुताई करना बेहद जरूरी है।

कैसे बनता है घोल

घोल बनाने के लिए सबसे पहले 5 लीटर पानी मे 100 ग्राम गुड़ उबाला जाता है। ठंडा होने के बाद घोल में 50 ग्राम बेसन मिलाकर कैप्सूल घोलना होता है। इसके बाद घोल को 10 दिन तक एक अंधेरे कमरे में रखा जाता है। पराली पर छिड़काव के लिए बायो-डिकम्पोजर घोल तैयार हो जाता है। इस घोल को जब पराली पर छिड़का जाता है तो 15 से 20 दिन के अंदर पराली गलनी शुरू हो जाती है। धीरे-धीरे ये पराली सड़कर खेत में खाद बन जाएगी। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ावा मिलता है, जो आने वाली फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। डिंकपोजर छिड़कने के बाद अवशेष और फसल को पलटना भी जरूरी है। इससे पराली गलने की प्रकिया में तेजी आती है।

खाद-बीज व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने नए नियम लागू

10वीं पास युवाओं के लिए खाद-बीज व्यापार शुरू करने का नया खुला द्वार

नई दिल्ली/भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार ने खाद-बीज उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नियमों में बदलाव करके रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया है। अब दसवीं पास युवाओं को भी खाद-बीज का व्यापार करने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए सरकार ने 15 दिन का पाठ्यक्रम बनाया है, जिसे पूरा करने के बाद युवा खाद-बीज की दुकान खोल सकेंगे। कृषि में स्नातक युवाओं के साथ-साथ 10वीं पास युवाओं को भी इस पहल से खाद-बीज व्यवसाय में प्रवेश का अवसर मिलेगा। यह कदम बिना किसी बड़ी चुनौती के युवाओं को रोजगार के अवसर देगा। खाद-बीज क्षेत्र में सरकार द्वारा दी गई सुविधा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम साबित हो सकती है और कृषि क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर सकती है।

अब खाद-बीज व्यापार में कम निवेश करके अधिक पैसा कमाने का तरीका बदल गया है। अब खाद-बीज व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। व्यावसायिक योग्यता हासिल करने के लिए खाद-बीज केंद्र में 12500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। यह कोर्स पूरा करना अनिवार्य है, और कोई भी इसे नहीं पूरा करेगा तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम खाद-बीज व्यापारियों को अधिक अनुभवी बनाएगा, जिससे वे बेहतर मार्केटिंग और उत्पादन तकनीक सीख सकेंगे। किसानों के अलावा व्यावसायिक उद्यमियों को इससे नई संभावनाएं मिलेंगी।

कृषि उत्पादों के व्यापार में युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी

केंद्र सरकार ने रोजगार को बढ़ाने के लिए नियमों को बदल दिया है। इसके परिणामस्वरूप, कृषि क्षेत्र में बीए पास और 10वीं पास युवाओं को खाद-बीज और कीटनाशक की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में आसानी हुई है। नए नियमों के अनुसार इन युवाओं को कृषि विज्ञान केंद्र में 15 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा। कोर्स पूरा करने के बाद उन्हें परीक्षा देनी होगी। उन्हें इसके उत्तरार्ध में प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसके बाद वे लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह नया नियम युवा उद्यमियों को मदद करेगा और कृषि उत्पादों के संचार में नई ऊर्जा भरेगा। इससे अधिक युवा स्वावलंबी बन सकेंगे और कृषि क्षेत्र में अपनी जगह बना सकेंगे। यह फैसला युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा करेगा और उन्हें नई दिशा में ले जाएगा।

10वीं पास होना जरूरी

कृषि और किसान कल्याण विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए 10 वीं पास होना ही आवश्यक रहेगा। इस क्षेत्र में काम करने के लिए पहले कृषि में बीएससी या कृषि में डिप्लोमा होना चाहिए था। अब 10वीं पास लोग भी कीटनाशक और खाद-बीज का व्यापार कर सकते हैं क्योंकि इस बाध्यता को हटा दिया गया है। खाद-बीज क्षेत्र में नई उम्मीदों की दिशा में यह निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है।

इन डाक्यूमेंट्स की होती है जरूरत

किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ती ब्याज दरों पर किसानों को मिलता है लाखों का लोन

नई दिल्ली/भोपाल। जागत गांव हमार

किसानों की मदद के लिए सरकार की तरफ से कई कई कार्य किए जा रहे हैं। जिसमें से एक किसान क्रेडिट कार्ड भी है। इस कार्ड के जरिए किसान भाइयों को बेहद कम ब्याज दर पर लोन मिलता है। इस कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले किसानों की उम्र कितनी होनी चाहिए। साथ ही किन दस्तावेजों की जरूरत होती है, ये हम आपको इस खबर के जरिए बताएंगे।

किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ती ब्याज दरों पर तीन लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल जाता है। इस लोन पर ब्याज दर 7 फीसदी से शुरू होती है। वहीं, वक्त पर लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज दर में 3 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाती है। इस तरह किसान क्रेडिट कार्ड से लिए जाने वाले ऋण पर केवल 4 फीसदी की ब्याज दर देनी होती है।

किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लेने के लिए किसान की उम्र 18 वर्ष से लेकर 75 वर्ष के बीच होनी चाहिए। किसान के पास कम से कम 2 एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए। साथ ही किसान भाइयों का बैंक खाता होना भी जरूरी है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए किसान को संबंधित बैंक की शाखा में जाना जरूरी है। किसान क्रेडिट कार्ड से किसान कृषि के कामों के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। इस लोन का इस्तेमाल किसान भाई खाद, बीज, कृषि मशीन, पशुपालन, मछली पालन आदि के लिए कर सकते हैं।

ये हैं जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, कृषि भूमि से जुड़े दस्तावेज बैंक खाते की जानकारी।

ये है वो मछली, जिसे घर में पालकर कर सकते हैं बिजनेस!

भोपाल। आजकल अलग-अलग प्रकार की खेती कर किसान भाई तगड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी मछली के बारे में बताएंगे जिसे पालकर आप तगड़ा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम निवेश में ही अच्छी कमाई दे सकता है। यदि आप मछली पालन का कार्य प्रारम्भ करना चाहते हैं, तो आपके लिए कतला मछली एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

देश में बड़ी मात्रा में मिलने वाली कतला मछली मीठे पानी में रहने वाली मछली है। ये खाने में काफी स्वादिष्ट होती है साथ ही इसकी ग्रोथ भी जल्दी होती है। इसलिए इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा रहती है। कतला मछली पालन के लिए आपको किसी बड़े तालाब या पोंड की जरूरत नहीं होती है।

अगर आप इस मछली को पलाना चाहते हैं तो आप इसे छोटे से टैंक या फिर गड्ढे में भी पाल सकते हैं। जबकि आप बड़े पैमाने पर कतला मछली पालन करना चाहते हैं, तो आपको एक बड़ा तालाब या पोंड बना सकते हैं। मछली पालन के लिए बीज आप किसी भी मछली पालन केंद्र से खरीद कर ला सकते हैं। मछली के बीज खरीदते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि बीज अच्छा और ताजा हो। मछली के लिए खाना आप बाजार से खरीद सकते हैं। मछली पालन के लिए पानी साफ व ताजा होना जरूरी है। पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भी पर्याप्त रहनी चाहिए। ये मछली करीब 6 से 8 महीने में तैयार हो जाती है। जिसके बाद आप इसे बेच सकते हैं। आप कतला मछली पालन से बढ़िया मुनाफा हासिल कर सकते हैं।

आवश्यक चीजें

मछली के बीज
खाना
पानी
ऑक्सीजन
तालाब या पोंड
क्या हैं लाभ
कम निवेश में अच्छी कमाई
जल्दी बढ़ती मछली
मार्केट में अच्छी मांग

सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करने, पानी की बर्बादी को कम करने और पानी की दक्षता में सुधार करने की कवायद

किसानों के लिए 5 बड़ी योजनाएं चला रही सरकार अब तक नहीं उठाया लाभ तो तत्काल करें आवेदन

नई दिल्ली/भोपाल। जागत गांव हमार

देश में किसानों के उत्थान के लिए कई सारी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का मकसद किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करना है। किसानों को इन योजनाओं के प्रति समय-समय पर जागरूक भी किया जाता है। लेकिन, आज भी कई किसान ऐसे हैं जो जानकारी न होने के कारण इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। भारत में किसानों के लिए चलाई जा रही अधिकतर योजनाओं के तहत किसानों को आर्थिक सहायता के साथ ही फसल का बीमा और अन्य सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। इस खबर में हम आपको सरकार की पांच बड़ी योजनाओं के बारे में बताएंगे, जो किसानों के लिए काफी उपयोगी साबित होंगी। ऐसे में अगर आप भी एक किसान हैं तो जानकारी लेने के बाद इन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना – प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को पीएम किसान योजना भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। जिसके तहत किसानों को हर साल तीन किस्तों में 6 हजार रुपए प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक किस्त में किसान को 2 हजार रुपए दिए जाते हैं। आप पीएम किसान पोर्टल पर आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर योजना के लिए आपका आवेदन सही पाया जाता है, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा।

प्रधानमंत्री के कृषि सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री के कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। केंद्र सरकार ने इस योजना को हर खेत को पानी के नाम लॉन्च किया था। हालांकि, अब इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नाम से जाना जाता है। यह सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, जो हर खेत को पानी योजना के तहत आती है। यह योजना सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करने, पानी की बर्बादी को कम करने और पानी के उपयोग में दक्षता में सुधार करने के लिए लागू की गई थी। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, वर्ष 2021-22 के लिए सूक्ष्म सिंचाई के तहत यह योजना लागू होती है।

किसान क्रेडिट कार्ड

किसान क्रेडिट कार्ड योजना को भारत सरकार, नाबार्ड एवं आरबीआई के द्वारा मिलकर 1998 में स्थापित किया गया था। हालांकि, 2020 में इस योजना में संशोधन करने के बाद इसे दोबारा लॉन्च किया गया। किसानों को केसीसी के अंतर्गत कम ब्याज पर ऋण प्रदान किया जाता है ताकि वे अपनी फसल की बुवाई और अन्य अतिरिक्त खर्चों का प्रबंधन कर सकें और जब फसल पक जाए तो कर्ज की राशि का भुगतान कर सकें। इसके अन्तर्गत देश के किसी भी किसान को आवेदन करने का विकल्प है।

फसल बीमा योजना

फसल बीमा योजना के तहत किसानों को कम प्रीमियम देकर उनकी फसल के बीमा का लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है और आपदा से प्रभावित फसल को सुरक्षित किया जाता है। इस विशेष योजना को 2016 में शुरु किया गया था और यह केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। सरकार इस योजना के माध्यम से आपदा से प्रभावित हुई फसल पर किसानों की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का लाभ देने के लिए हुई थी। इस योजना के अंतर्गत, 18 से 40 साल की आयु के किसान किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए हर महीने आपको 55 रुपए से 200 रुपए का प्रीमियम जमा करना होगा। वहीं, 60 साल के बाद आपको पेंशन के रूप में 3 हजार रुपए की राशि प्राप्त होगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको 20 सालों तक किस्त जमा करनी होगी।

ऐसे उठाएं सरकार की विशेष ट्रेनिंग का लाभ

जिरेनियम और अन्य कई तरह की फसलों की खेती के लिए देंगे प्रशिक्षण

एरोमैटिक फसलों की खेती से आप भी कमा सकते हैं लाखों

नई दिल्ली/भोपाल। जागत गांव हमार

हमारे देश के किसानों के द्वारा कई तरह की फसलों की खेती की जाती हैं। ताकि वह कम समय में अपनी फसल से अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकें। देखा जाए तो किसान कम खर्च में होने वाले वाली फसलों की तरफ बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार के द्वारा भी किसानों की मदद के लिए एक मिशन शुरू किया गया है जिसका नाम एरोमा मिशन है। सरकार के इस मिशन के तहत सुगंधित फसलों की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। एरोमा मिशन के तहत देश के किसानों को सुगंधित फसलों की खेती के लिए ट्रेनिंग की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएंगी। यह ट्रेनिंग सीएसआईआर-केंद्रीय औषधीय एवं सगंध अनुसंधान संस्थान के द्वारा किसानों को उपलब्ध होगी।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से एरोमा मिशन के तहत देश के किसानों को लेमन ग्रास, खस, मिंट, जिरेनियम, अश्वगंधा और अन्य कई तरह की एरोमैटिक फसलों की खेती के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसे में आइए इन फसलों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

टॉप पांच एरोमैटिक फसल

लेमन ग्रास – इसका इस्तेमाल सबसे अधिक परफ्यूम, साबुन, निरमा, डिटर्जेंट, तेल, हेयर ऑयल, मच्छर लोशन, सिरदर्द की दवा आदि कई तरह की उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। किसान लेमन ग्रास की खेती को साल में कभी भी कर सकते हैं।

जिरेनियम – जिरेनियम के पौधे से औषधीय दवाएं और साबुन, इत्र और सौंदर्य के प्रॉडक्ट बनाने में किया जाता है। देखा जाए तो भारत में कुछ ही सालों से जिरेनियम की खेती की जा रही है। इसे पहले यह खेती विदेशी में की जाती थी। जिरेनियम की खेती कम पानी में अच्छा उत्पादन देती है।

मेंथा – इस खेती को देश के किसान के बीच में कई तरह के नामों से जाना जाता है। इन्हीं नाम में सबसे अधिक लोकप्रिय मिंट और मेंथा है। इसका इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स, टूथपेस्ट और अन्य कई तरह के उत्पादों को तैयार किया जाता है। देखा जाए तो भारत मेंथा तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।

खस – यह एक ऐसी खेती है, जिससे किसान कम लागत में हर एक तरह से मुनाफा पा सकता है। कहने का मतलब है कि किसान खस के फूल, जड़ और पत्तियों से भी बाजार में अच्छी कमाई कर सकते हैं। क्योंकि इसका उपयोग महंगे इत्र, सुगंधित पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधनों तथा दवाइयों को बनाने में सबसे अधिक किया जाता है।

क्यों हल्दी की खेती को माना जाता है कमाई वाली फसल, यहां समझिए पूरा गणित

नई दिल्ली/भोपाल। जागत गांव हमार

देश के लगभग हर घर में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खेती कर किसान भाई अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जिसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है, आइए जानते हैं।

बताते चलें कि हल्दी की खेती को कमाई वाली फसल कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत से कार्यों में इस्तेमाल होने वाली फसल है। जिसकी मांग हमेशा बनी रहती है। हल्दी का इस्तेमाल मसाले, औषधि, ब्यूटी प्रोडक्ट्स व अन्य कई उत्पादों में होता है। इसके साथ ही हल्दी की खेती के दौरान अधिक पानी या फिर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक ऐसी फसल है जो कम लागत में उग सकती है और इससे अच्छी आमदनी की जा सकती है। यदि आप एक हेक्टेयर जगह में हल्दी की खेती करने की सोच रहे हैं तो करीब-करीब 10,000 रुपए के बीज, 10,000 रुपए की खाद व मजदूरी शुल्क जो उस समय लागू हो वह आपको देना होगा। हल्दी की खेती से होने वाली आय मुख्य रूप से उत्पादन पर निर्भर होती है। एक हेक्टेयर में हल्दी का औसत उत्पादन 20-25 क्विंटल तक का होता है। यदि हल्दी का भाव 200 रुपए किलो है, तो एक हेक्टेयर में हल्दी की खेती से करीब 5 लाख तक की कमाई की जा सकती है।

किन बातों का रखें ध्यान

हल्दी की खेती करने के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी को चुनें। इसके खेती करने के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल करें। हल्दी की खेती के दौरान कीटों और बीमारियों से बचाव के लिए उचित उपाय करें। फसल को सही समय पर खेत से निकाल लें।

हल्दी की है बेहद डिमांड

बाजार में हल्दी की काफी डिमांड है। भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी हल्दी की काफी मांग है। आप हल्दी को ऑनलाइन प्लेटफार्म के जरिए भी अच्छे दामों में बेच सकते हैं।

खेती-किसानी में बढ़ती लागत को देखते हुए केंद्र सरकार ने लिया बड़ा लाभकारी फैसला

अब ड्रोन दीदी बनकर महिलाएं कर सकेंगी बढ़िया कमाई

नई दिल्ली/भोपाल। जागत गांव हमार

खेती-किसानी में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इससे महिलाएं तो सशक्त हो रही हैं। साथ ही उनका परिवार भी आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। खेती-किसानी में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े इसके लिए सरकार भी अपनी तरफ से कई योजनाएं लॉन्च कर रही है। लखपति दीदी योजना भी ऐसे ही प्रयास का हिस्सा थी। अब केंद्र सरकार ने खेतिहर महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने विकास भारत संकल्प यात्रा के प्रतिभागियों से भी बात चीत की। ड्रोन दीदी योजना के तहत, अगले कुछ वर्षों में सरकार ने 1261 करोड़ रुपए खर्च कर 15,000 महिला एसएचजी को ड्रोन मुहैया कराने का फैसला किया है।

ड्रोन उड़ाने पर महिलाओं को मिलेंगे महीने के 15000 रुपए

इस ड्रोन योजना के माध्यम से ड्रोन उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव में सहायता मिलेगी। इसके लिए इन महिलाओं को करीब 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन पायलट और सह-पायलट को हर महीने ड्रोन उड़ाने के लिए निश्चित राशि मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को ड्रोन खरीदने पर उसके लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम 8 लाख रुपए दिए जाएंगे।

ड्रोन का उपयोग खेती के लिए कितनी फायदेमंद

किसी भी फसल में अचानक बीमारी आ जाने के कारण स्प्रे करना असंभव होता था । अब इस ड्रोन तकनीक से एक बार में काफी बड़े एरिया में छिड़काव किया जा सकेगा। इससे दवा और समय दोनों की बचत होगी। पहले समय के अभाव में किसान दवा का छिड़काव नहीं कर पाते थे। जिससे फसलों में कीड़े लग जाते थे और फसलें बर्बाद होती थीं, मगर अब ड्रोन से एक भी बार में ज्यादा एकड़ में छिड़काव हो सकेगा।

-राजस्थान में तो चुनाव से पहले ही छोड़ दिया था मैदान

मप्र सहित तीन राज्यों के कृषि मंत्रियों की करारी हार

भोपाल। जागत गांव हमार

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनावों में कई उलटफेर देखने को मिले हैं। इसमें कई मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है. लेकिन, एक बात दिलचस्प है कि तीन राज्यों में कृषि मंत्री चुनाव हार गए हैं। जबकि एक राज्य में कृषि विभाग संभालने वाले नेताजी पहले ही मैदान छोड़ गए थे। सत्ता भाजपा, कांग्रेस की रही हो या फिर बीआरएस की, एक में भी कृषि मंत्री की कुर्सी नहीं बची। सवाल यह है कि क्या किसी एक भी राज्य के कृषि मंत्री ने किसानों के लिए इतना काम नहीं किया था कि जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया पहले ही मैदान छोड़ चुके थे। उन्होंने इस बार चुनाव ही नहीं लड़ा था। हालांकि, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जरूर मध्य प्रदेश की दिमनी विधानसभा सीट पर बंपर वोटों से चुनाव जीत गए हैं। बहरहाल, अब हम आते हैं राज्यों के कृषि मंत्रियों की हार पर। हो सकता है कि यह महज एक संयोग ही हो, लेकिन अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कृषि मंत्री अपने ही क्षेत्र की जनता में छाप नहीं छोड़ सके। किसानों की नाराजगी इन पर भारी पड़ी, जबकि, कृषि ऐसा विषय है जिस पर भाजपा, कांग्रेस और बीआरएस तीनों फोकस कर रहे थे। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में तो सरकार ने खेती-किसानी पर विशेष जोर दिया हुआ था।

इन कृषि मंत्रियों को मिली शिकस्त

मध्य प्रदेश: भले ही भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है, लेकिन उसके दिग्गज नेता कमल पटेल चुनाव हार गए हैं। हरदा विधानसभा क्षेत्र में उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी आरके दोगने खड़े थे। भाजपा ने गेहूं, धान की एमएसपी पर बोनस देने की घोषणा की, लेकिन कमल पटेल अपने ही क्षेत्र में मोदी की गारंटी के नारे को भुना नहीं पाए।

छत्तीसगढ़: दुर्ग जिले की हाई प्रोफाइल सीट दुर्ग ग्रामीण पर राज्य के गृह और कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू को हार का सामना करना पड़ा है। इस बुजुर्ग नेता को भाजपा के ललित चंद्राकर ने पराजित किया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 3100 तो कांग्रेस ने 3200 रुपए क्विंटल की दर पर धान खरीदने का वादा किया था।

तेलंगाना: कृषि मंत्री एस निरंजन रेड्डी केसीआर के खासमखास लोगों में गिने जाते थे। वो वानापर्थी विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरे थे। उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस प्रत्याशी मेघा रेड्डी ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। मेघा रेड्डी को कुल 107115 मत मिले जबकि, निरंजन रेड्डी को 81795 मत मिले हैं।

राजस्थान: कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने चुनाव ही नहीं लड़ा था। शायद उन्होंने हालात पहले ही भांप लिया था। वो झोटवाड़ा सीट से लड़ते रहे हैं। यहां कटारिया का काफी विरोध था। इस सीट पर बीजेपी के कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जीत दर्ज की है। हालांकि, खेती-किसानी से ही जुड़े गहलोत सरकार के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना चुनाव हार गए हैं।

-जीती भाजपा: मोदी की गारंटी के फीका कांग्रेस का वचन

गेहूं-धान और किसान से भाजपा को मिला विजयी आशीर्वाद

भोपाल। सियासत में संख्या बल सबसे अहम होता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीन सूबों में करीब सवा दो करोड़ किसान परिवार हैं। इसका मतलब करीब 9 करोड़ लोग। वो लोग जो गांवों में रहते हैं और सबसे ज्यादा वोट करते हैं। भाजपा ने कुछ इसी तरह की गणित से इन तीनों सूबों के विधानसभा चुनावों में किसानों के मुद्दों पर फोकस किया। खासतौर पर रबी और खरीफ सीजन की प्रमुख फसलों के दाम पर। जिस न मिलने का किसान अक्सर रोना रोते रहते हैं। पार्टी के रणनीतिकारों ने 2,700 रुपए क्विंटल पर गेहूं और 3100 रुपए के दाम पर धान खरीदने का वादा किया। जबकि 2024-25 के लिए गेहूं का एमएसपी 2275 और धान की एमएसपी सिर्फ 2183 रुपए क्विंटल ही है। धान, गेहूं का इतना दाम मिलने की मोदी की गारंटी पर किसान खुश हो गए और उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोटों की बारिश कर दी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विस चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत के पीछे चार बड़े कारण सामने आए हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, फ्री राशन, महिलाओं और खेती-किसानी पर फोकस से जीत की राह आसान हो गई। दरअसल, तीनों सूबों में पार्टी ने गेहूं, धान और किसान को तवज्जो दी। यहां तक कि तीनों के संकल्प पत्र में वादों की जो झड़ी लगाई गई है उसके पहले पन्ने में किसानों के मुद्दों को ही जगह दी गई है।

मप्र में 12 हजार किसान निधि

किसान नेताओं को कहना है कि किसानों से जुड़े वादों ने भाजपा को जिताने में अहम भूमिका अदा की। भाजपा ने 2,700 रुपए क्विंटल पर गेहूं और 3100 रुपए के दाम पर धान खरीदने की घोषणा की हुई है। यह लगभग सी-2 कॉस्ट की एमएसपी जितनी रकम है। किसानों को इतना दाम मिलेगा तो फिर किसान संगठनों का सी-2 वाली एमएसपी का मुद्दा खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार हर परिवार को लाड़ली बहना योजना के तहत सालाना 12,000 रुपए और किसान निधि के 12000 रुपए दे रही है। साथ में राशन फ्री है। ऊपर से धान, गेहूं की खरीद पर बोनस देने की घोषणा ने वोटरों को भाजपा की ओर खींचा और कांग्रेस को हाशिए पर खड़ा कर दिया।

तीनों राज्यों में किसानों के आए अच्छे दिन

राजस्थान: पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 12,000 सालाना मिलेंगे। अभी 6000 रुपए मिल रहे हैं। अब पार्टी की जीत के बाद इतनी ही रकम राज्य सरकार भी देगी। भाजपा ने किसानों से वादा किया है कि वो गेहूं की फसल को एमएसपी के ऊपर बोनस देकर 2,700 प्रति क्विंटल के दाम पर खरीदेगी। राजस्थान देश का 10 फीसदी गेहूं उत्पादन करता है। पार्टी ने एमएसपी पर ज्वार एवं बाजरा की खरीद की व्यवस्था करने का भरोसा दिलाया है। श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना होगी। राजस्थान देश का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक सूबा है। लेकिन एमएसपी पर इसकी खरीद नहीं हो रही थी।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)